अपीलीय अपराध

न्यायधीश मान मोहन सिंह गुजराल और न्यायधीश एस.सी. मितल के समक्ष।

हरियाणा राज्य,-अपीलकर्ता

बनाम

प्रकाश चंद,-प्रतिवादी।

1969 की आपराधिक अपील संख्या 1352।

6 जनवरी, 1971।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का X, 1967 के XXXVI द्वारा संशोधित) - धारा 7-अनजाने में उल्लंघन- क्या दंडनीय है-हरियाणा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल डीलर लाइसेंसिंग आदेश (1967)-आदेश-के तहत दिए गए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है -इस तरह के आदेश में लाइसेंसधारी के पास मौजूद वनस्पति तेल के स्टॉक को सात दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान है - ऐसे लाइसेंसधारक के खिलाफ बिना लाइसेंस के बिक्री के लिए वनस्पति घी के भंडारण का आरोप-अभियुक्त-क्या लाइसेंसधारी को रद्दीकरण आदेश की रसीद की तारीख साबित करनी होगी।

यह निर्धारित किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1), जैसा कि 1967 में इसके संशोधन के बाद कायम है, ने स्पष्ट रूप से आपराधिक मनःस्थिति के तत्व को खारिज कर दिया है। इसलिए, इससे पता चलता है कि चाहे धारा 7 में उल्लिखित उल्लंघन जानबूझकर किया गया हो या नहीं, यह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत दंडनीय हो जाता है। (पैरा 4)

यह निर्धारित किया गया कि, जहां हरियाणा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1967 के तहत लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर समर्थन प्रदान करता है कि लाइसेंसधारी के पास वनस्पति तेल का स्टॉक, यदि कोई हो, लाइसेंसधारी द्वारा इसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए, अभियोजन पक्ष पर उस तारीख को साबित करना अनिवार्य है जिस दिन लाइसेंसधारी को ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त होती है और यह की आदेश के तहत लाइसेंस के बिना बिक्री के लिए वनस्पति घी के भंडारण के आरोप को साबित करने के लिए उसे अपने स्टॉक का निपटान करने की सात दिनों की सीमा दी गई थी और वह समय सीमा समाप्त हो गई है। (पैरा 5).

श्री ए. एन. मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा,

अपीलकर्ता के लिए।

आर. एन.मित्तल, एक वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

न्यायधीश एस. सी. मित्तल–(1) यह अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के प्रकाश चंद को हरियाणा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1967 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत लगे आरोप में बरी करने के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

(2) मुख्य तथ्य यह हैं कि प्रकाश चंद का लाइसेंस उपरोक्त आदेश के तहत जारी किया गया था, 13 अगस्त, 1968 को जिला मजिस्ट्रेट, गुड़गांव द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसकी जानकारी होने पर, प्रकाश चंद ने अगले 28 तारीख को अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड, गाजियाबाद को टेलीग्राम एक्ज़िबिट डी.ए./1 भेजा और उसे ट्रक न भेजने का निर्देश दिया, लेकिन टेलीग्राम प्राप्त होने से पहले, सब्जी घी के टिन से भरा ट्रक गाजियाबाद से जा चुका था। यह 29 तारीख को प्रकाश (चंद) के व्यवसाय स्थल पलवल पहुंचा। उस समय प्रकाश चंद मौजूद नहीं थे और उनके बेटे के विरोध के बावजूद ट्रक को उतार दिया गया और सामान प्रकाश चंद के गोदाम में रख दिया गया। 31 अगस्त, 1968 को उप-निरीक्षक मान सिंह द्वारा गोदाम पर छापा मारा गया और वहां से 500 टिन वनस्पति घी बरामद किया गया। पूरी सामग्री पर विचार करने पर रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश चंद की ओर से कोई आपराधिक मामला नहीं था और यह स्थापित नहीं हुआ था कि प्रकाश चंद को अपने गोदाम में घी के भंडारण के बारे में जानकारी थी। नाथूलाल v. मध्य प्रदेश राज्य[1] , में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया, "मध्य प्रदेश खाद्यान्न डीलर लाइसेंसिंग आदेश, 1958, की धारा 3 के उल्लंघन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 10 ऑफ 1955 की धारा 7 के तहत अपराध आवश्यक रूप से अपराध के एक घटक के रूप में दोषी दिमाग को शामिल करता है। अधिनियम के दायरे को ध्यान में रखते हुए यह मानना वैध होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी आदेश की उलंघना अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध है ।" इस अधिकार पर भरोसा करते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित निर्णय पारित किया।

(3) विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने पहले प्रचार किया हमें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब लागू नहीं होगा, क्योंकि, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 को 1967 के अधिनियम XXXVI द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले, धारा 7 की उपधारा (1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था: –

"यदि कोई व्यक्ति धारा 3–(ए) के तहत दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा... ....."

जैसा कि संशोधित है, धारा 7 की उपधारा (1) इस प्रकार है: -

"यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा, धारा 3-(ए>) के तहत दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। ..... "

(अनुभाग का शेष भाग हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है)।

(4) धारा 7(1), जैसा कि अब है, ने 'अपराधिक मनोस्थिति ' के तत्व को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, क्योंकि, शब्द "या अन्यथा" सभी व्यापक हैं। इसलिए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 7 में उल्लिखित उल्लंघन चाहे जानबूझकर, जानबूझकर किया गया हो या नहीं, यह धारा 7 की उपधारा (1) के तहत दंडनीय हो

[1] A.I.R 1966 SC 43

जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट का ध्यान ऊपर उल्लिखित संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। ऐसा होने पर, जिस आधार पर आक्षेपित निर्णय आधारित है, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(5) मामले का दूसरा पहलू यह है कि आदेश प्रदर्श पी.ई. के तहत समर्थन का प्रासंगिक भाग, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ने प्रकाश चंद का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो इस प्रकार है: –

"एक प्रति मैसर्स प्रकाश चंद ध्रुव कुमार, पलवल, को तत्काल अनुपालन हेतु भेज दी गई है। वनस्पति तेल का स्टॉक, यदि कोई हो, तो उसका आदेश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए।"

ऊपर उद्धृत समर्थन के मद्देनजर, दंडात्मक आवेदन के लिए प्रकाश चंद के खिलाफ हरियाणा हाइड्रोजनीकृत सब्जी तेल डीलर लाइसेंसिंग आदेश, 1967 के प्रावधानों के अनुसार, अभियोजन पक्ष पर उस तारीख को साबित करना अनिवार्य था जिस दिन प्रकाश चंद को आदेश प्रदर्शनी पी.ई. की प्रति प्राप्त हुई थी। और यह कि उसे अपने स्टॉक को निपटाने के लिए दी गई सात दिन की सीमा महत्वपूर्ण तारीख, यानी 31 अगस्त, 1968 को समाप्त हो गई थी। उक्त दो आवश्यकताएँ को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री पर हमारा ध्यान नहीं गया है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रकाश चंद को किसी भी कीमत पर, 28 अगस्त, 1968 को लाइसेंस रद्द करने की जानकारी थी, जिस तारीख को उन्होंने उपर्युक्त कंपनी कोटेलीग्राफ़िक रूप से ट्रक को ना भेजने के लिए निर्देश दिया था । पृष्ठांकन में जो निर्देशित किया गया है, उसके प्रकाश में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उसके लाइसेंस को रद्द करना का आदेश प्रदर्शनी पी.ई. की प्रति की प्राप्ति के सात दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होना था। ऐसा होने पर, इस तथ्य की मात्र जानकारी कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, कानूनन अभियोजन पक्ष को उसके खिलाफ लाइसेंस के बिना बिक्री के लिए वनस्पति घी के भंडारण के आरोप को साबित करने में मदद नहीं करेगा।

उपरोक्त कारणों से , हम अपील खारिज करते हैं।

न्यायधीश एम एम मोहन सिंह उजराल,- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा